तिब्बत का अर्थ हैं उ–त्सांग, खम तथा अम्दो प्रान्त । तिब्बत को केवल तिब्बत स्वायत्तशसी क्षेत्र समझना अनुचित और भ्रामक है ।)

भू–क्षेत्र

25 लाख वर्ग कि0 मी0 जिसमें उ–त्सांग, खम तथा अम्दो प्रान्त शामिल हैं। तिब्बती स्वायतशसी क्षेत्र में समपूर्ण उ–त्सांग और खम का एक छोटा–सा भाग शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 12 लाख वर्ग कि0 मी0 हैं अधिकतर तिब्बत ''तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र'' से बाहर हैं।

प्रशासन

चीनी आधिपत्य के अधीन तिब्बत निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों मे बंटा हुआ है :

1. तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र
2. छिंघाई प्रान्त
3. गांसु प्रान्त में टियांसु तिब्बती स्वायत्तशासी स्थानीय प्रशासनिक खण्ड तथा गन्नन तिब्बती स्वायत्तशासी प्रशासनिक अधिकारिक क्षेत्र।
4. आबा तिब्बती–छयांग स्वायत्तशासी प्रशासनिक अधिकारिक क्षेत्र तथा मिली तिब्बती स्वायत्तशासी स्थानीय प्रशासनिक खण्ड जो कि सिचुआन प्रान्त में स्थित हैं।
5. युन्नान प्रान्त में देचेन तिब्बती स्वायत्तशासी प्रशासनिक अधिकारिक क्षेत्र।

जनसंख्या

तिब्बत की कुल आबादी 60 लाख हैं, जिसमें से 20.9 लाख लोग तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में रहते हैं और बाकी तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के बाहर समपूर्ण तिब्बत में फैले हुए हैं।

निर्वासन में तिब्बती समुदाय

- **जनसंख्या** : लगभग 111,170 (विश्व–व्यापी तिब्बती जनसंख्या का अनुमान भारत : 85000, नेपाल : 14000, भूटन : 1600, स्विटजरलैण्ट : 1540, शेष यूरोप : 640, स्कैण्डीनेविया : 1000, अमरीका और कनाडा : 7000 जापान : 60 तायवान : 1000, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड : 220) (योजना परिषद, धर्मशाला द्वारा 1998 में किए गए तिब्बती जनसंख्या सम्बन्धी सर्वेक्षण पर आधारित।)
- **तिब्बत की निर्वासित सरकार** : तिब्बती मूल्यों से युक्त लोकतांत्रिक सरकार द्वारा शासित । इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधान मण्डल तथा कार्यपालिका व मंत्रिमण्डल जो संसद के प्रति सीधे उतरदायी हैं।
- **संविधान** : निर्वासित तिब्बती समुदाय का चार्टर
- **प्रमुख गैर सरकारी संगठन** : तिब्बती यूवा कॉग्रेस, तिब्बती महिला संगठन, तिब्बती मानवमधिकर व लोकतान्त्रिक केन्द्र, तिब्बती संसदीय एंव नीति शोध केन्द्र, एन डी पी टी, तिब्बती यूनाइटेड ऐसोसिऐशन, गु–चु–सुम, दो–तोए ऐसोसियेशन, दो–में ऐसोसियेशन, यू–त्सांग ऐसोसियेशन, न्यारी ऐसोसियेशन ।
- **तिब्बती कार्यालय** : तिब्बत के दूतावास नई दिल्ली, काठमाण्डू, न्यूयॉर्क, लन्दन, पैरिस, जेनेवा, ब्रसैल्स, मास्को, कैनबरा, टोक्यो, प्रोटोरिया तथा ताइपेइ में स्थित हैं।

- **जीविका** : खेती, खेती पर आधारित उद्योग, स्वैटर बेचना, हस्तकला का निर्यात तथा कुछ अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उपक्रम।
- **शिक्षा** : स्कूल जाने योग्य बच्चों में से 85 से 90 प्रतिशत का स्कूलों में पंजीकरण। इस समय 106 नर्सरी स्कूल, 87 प्राथमिक, 44 मिडल, 21 सैकेण्डरी तथा 13 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल हैं, जिनमें कुल 25000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं।

तिब्बत पर चीनी कब्जे का एक अवलोकन :

- 12 लाख से भी अधिक तिब्बती मारे जा चुके हैं।
- 6000 से भी अधिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थान नष्ट किए जा चुके हैं।
- सैकड़ो तिब्बती मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने के आरोप में जेलों में बन्द हैं।
- तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों तथा कोमल पर्यावरण को बुरी तरह नष्ट कर दिया गया हैं।
- यह एक प्रमाणिक तथ्य है कि तिब्बत को आणविक कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हैं।
- तिब्बत में तिब्बती लोगों की आबादी (60 लाख) से अधिक चीनी लोगों की आबादी (75 लाख) हो गई हैं।
- तिब्बत जो कभी भारत और चीन के बीच का एक शांतिपूर्ण मध्यस्थ राज्य था एक व्यापक सैनिक अडडें में बदल दिया गया हैं।

तिब्बत पर भारतीय नेताओं के उद्‌गार

''यदि भारत ने तिब्बत को मान्यता प्रदान की होती, जैसा कि उसने 1949 में चीनी गणराज्य को प्रदान की थी, तो आज भारत–चीन सीमा विवाद न होकर तिब्बत–चीन सीमा विवाद होता। माओ को पंचशील में थोड़ा भी विश्वास नहीं है और यह भी कि राजनीति में पंचशील का कोई स्थान नहीं होता। चीन को ल्हासा पर अधिकार करने देकर प्रधानमंत्री ने चीनी लोगों को अपनी सेनाएं भारत की सीमा पर ले आने में पूरी सहायता पहुंचाई है।''

— डा. भीमराव अंबेडकर 1954

मुझे मानना पड़ता है कि सत्य को झूठ बताने और झूठ को सत्य प्रतीत कराने के चीनी प्रयास ने मुझे भौंचक्का कर दिया है। वे उस जीमन पर चढ़ आए हैं जो पिछले दस हजार वर्षो में भी कभी उसके पास नहीं थी। केवल तिब्बत पर कब्जे के माध्यम से चीन सरकार यह दावे कर रही हैं जो स्वयं केवल 12 वर्ष से अस्तित्व में है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू, भारतीय प्रधानमंत्री
–1962 में भारत पर चीनी हमले के बाद का एक वक्तव्य

चीन सरकार ने तिब्बत के बारे में शांतिपूर्वक इरादों की बात करके हमें बहकाने की कोशिश की है। इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि हमसे पत्राचार की अवधि में वे तिब्बत पर आक्रमाण की तैयारी में लगे रहे । दुख की बात है कि तिब्बती हममें विश्वास करते हैं, उन्होंने हमसे मार्गनिर्देश चाहा, और हम उन्हें चीनी कूटनीति की दुर्भावना के जाल से निकालने में नाकम रहे हैं।''

–सरदार वल्लभभाई पटेल,
1950 में तत्कालीन उप–प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री

''मेरा दिल तो तिब्बत की उस घोर पीड़ा में उसकी तरफ था मगर मैं कुछ करने में नाकाम रहा। इसलिए कि तब मैं खुद ज्ञानहीन मार्क्सवादी होने के कारण तथ्यों को पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन अपने हिस्से की जिम्मेदारी से बचने का मेरे पास कोई बहाना नहीं हैं। आज मैं अपना वह दोष बड़े दुख के साथ, अपने अंतःकारण से स्वीकार करता हूं।''

— आर. के. करंजिया, 1995, संपादक 'ब्लिट्ज'

आज के दौर में आप तिब्बत के लिए क्या कर सकते हैं ?

- अपने इलाके मे ''तिब्बत समर्थक समूह'' की स्थापना तथा आस–पास के लोगो को तिब्बत और तिब्बती लोगों के विषय में बताना।
- समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के जरियें तिब्बती लोगों की न्यायिक अधिकारों का समर्थन करना।
- अपने क्षेत्र के संसद–सदस्यों को तिब्बत के बारे में सूचित करना तथा उनसे तिब्बत के मुददे को संसद में उठाने का अनुरोध करना।
- भारत सरकार से जनवादी चीन की सरकार तथा तिब्बत की निर्वासित सरकार के बीच उचित बातचीत के लिए माहौल तैयार करने के लिए अनुरोध करना।

भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र – द्वारा जारी
एच–10 दूसरी मंजिल, लाजपत नगर–3,
नई दिल्ली–110024 भारत
फोन नः 91–11–29841569
फैक्स : 91–11–29840966
E-mail : bharatibbat@yahoo.com
Web : www.indiatibet.org

Vee Enn Print-O-Pac # 011-66605040

तिब्बत एक तथ्य

भूमिका

2000 वर्षो से भी अधिक समय तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रुप में दो एशियाई ताकतों भारत व चीन के बीच विधमान रहा है। लेकिन 1949 में सम्यवादी चीन ने इसपर आक्रमाण कर दिया और 1959 तक समुचे तिब्बत पर चीन ने आवैध कब्ज़ा कर लिया। इसके परिणाम स्वारुप परम पावन दलाई लामा जी और उनके साथ लगभग 85,000 तिब्बतियों को निर्वासित होकर भारत आना पड़ा ।

आज, निर्वासित होकर भारत में रहने वाले एक लाख से अधिक तिब्बती लोग दृढ़विश्वास के साथ उस दिन का इन्तज़ार कर रहे है जब वह सम्मान व गौरव के साथ अपनी मात्र भूमि वापिस लौट सकेंगे। तिब्बती समुदाय ने साम्यवादी चीन के कब्जे में बहुत अत्याचार और तबाही झेली हैं। अब तक 12 लाख से भी अधिक तिब्बती लोग शहीद हो गये हैं और 6 हजार धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थान तथा राष्ट्रीय विरासत के स्मारक नष्ट कर दिए गए हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के 20 वें आधिवेशन मे भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के मुखिया श्री ज़कारिया के अनुसार **''तिब्बतियों के साथ जिस निर्दयतापूर्ण ढंग से व्यवहार किया गया है उसकी मिसालें दुनिया के इतिहास में बहुत कम हैं।''**

निर्वासन में महामहिम दलाई लामा जी के नेतृत्व में तिब्बती समुदाय ने अपनी अदभुत संस्कृति तथा आध्यात्मिक विरासत की रक्षा एंव अपने न्यायपूर्ण आधिकार की प्राप्ति के संघर्ष में वैचारिक प्रतिबद्धता, समर्पण, साहस, धीरज, दुर्दशा तथा दृढ़ संकल्प का प्रशासनीय परिचय दिया हैं भारत ने इस छोटे से निर्वासित समुदाय को जगह दी, आजादी दी और बहुत उदारता से इनका स्वागत किया, जिसके बिना इस समुदाय के लिए अपनी पहचान बनाऐ रखना और अपने उदेश्य को लेकर बढना मुश्किल हो जाता।

प्रत्येक देशभक्त भारतीय के लिए तिब्बत का मुद्‌दा सिर्फ तिब्बती लोगों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए ही चिन्ता का विषय नहीं हैं भारत के साथ तिब्बत के गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक सम्बन्धों के अतिरिक्त तिब्बत का मुददा भारत की सुरक्षा और अन्य हितों पर सीधा प्रभाव डालता हैं।

तिब्बत की समस्या का एक सीधा–सच्चा तथा सम्मानीय समाधान न केवल चीन, भारत और तिब्बत के हित में होगा। बल्कि इस उपमहाद्वीय में शांति और मित्रता के हित में भी होगा। महामहिम दलाई लामा द्वारा प्रस्तुत शांति प्रस्ताव में सभी के सामान्य कल्याण से सम्बन्धित सभी प्रकार के मुद्‌दों को ध्यान मे रखा गया हैं। उन्हें अहिंसा का समर्थन करने के लिए न सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया बल्कि दुनिया भर के नेताओं, सरकारों और संसद–सदस्यों नें इस प्रस्ताव को एक फायदेमंद और आपसी समाधान के लिए निर्मित एक रचनात्मक प्रस्ताव माना हैं। भारतीय साम्यवादी दल सहित अनेक भारतीय राजनैतिक दलों के 212 संसद–सदस्यों ने इन प्रयासों का समर्थन करते हुए कहा **''हम महामहिम दलाई लामा के उस पॅाच सूत्रीय प्रस्ताव का पूरा–पूरा समर्थन करते हैं जो हमारे विचार में तिब्बत के महत्वपूर्ण प्रश्न को सुलझाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हैं और जो तिब्बती लोगो की परेशानियां दूर करे तथा क्षेत्रीय तनाव को खत्म कर देगा।''**

भारत के लिए चिन्ता का विषय

इतिहास गवाह है कि भारत के साथ तिब्बत के सम्बन्ध सदा नजदीकी और दोस्ताना रहें है, खासकर सातवीं शताब्दीं मे, जब भारत से बौद्ध धर्म आया । तिब्बत पर चीनी कब्जा होते ही इतिहास में पहली बार हिमालय की पर्वतीय सीमा पर भारत और चीन की सैनिकों ने एक–दूसरे का सामना किया। भारत के प्रमुख नेताओं जैसे डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, डॉ0 राम मनोहर लोहियाए, लोक नायक जय प्रकाश नारायण, डॉ0 भीम राव अम्बेडकर, सरदार पटेल, पं0 दीन दयाल उपाध्याय, आचार्य रघुवीर आदि ने तिब्बत के मुददे पर तथा इसके भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी। इस नई भौगोलिक, राजनैतिक और कूटनीतिक परिस्थिति में निम्नलिखित मुददे भारत के राष्ट्रीय हित पर सीधा प्रभाव डालतें हैं।

तिब्बत पठार का सैन्यीकरण

चीन ने भारत और चीन के बीच स्थित इस राष्ट्र का एक व्यापक सैनिक–क्षेत्र में बदल दिया जो कभी एक शॉतिपूर्ण क्षेत्र था। तिब्बती पठार के सैन्यीकरण ने उस क्षेत्र के भौगोलिक–राजनैतिक संतुलन को प्रभावित किया हैं जिससे अन्तराष्ट्रीय स्तर पर और खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीय में तनाव बढ़ गया हैं।

तिब्बत में चीनी सेना की मौजूदगी इस प्रकार हैं :

तीन से पॉच लाख सैनिक, जिनमें से आधिकतर भारतीय सीमा के आस–पास हैं।

- 17 गुप्त राडार स्टेशन
- 14 सैनिक हवाई अडडे
- 8 प्रक्षोपास्त्र ठिकाने जिसमें 8 अन्तरमहाद्वीपपीय शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र
- 17 मध्यम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र
- 20 कम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र

इसके अतिरिक्त चीन तिब्बत को रासायनिक युद्ध के अभ्यास के लिए तथा बड़ी धन राशि के बदले में अन्य देशों के आणुविक कचरे को फेंकने के लिए भी इस्तेमाल करता रहा हैं।

यही नहीं भारत के राष्ट्रीय संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा, जो की 1959 से भारत–तिब्बत सीमा की सुरक्षा पर खर्च होता रहा हैं। ये संसाधन विकासात्मक परियोजनाओं पर भी खर्च किए जा सकते थे।

रेल परियोजना तथा उसका भारत पर प्रभाव :

20 जून 2001 के चीन ने गोर्मो से ल्हासा को जोड़ने वाली 1,118 कि0 मी0 लम्बे रेल मार्ग की परियोजना शुरु की। 10 अगस्त 2001 को न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए साक्षत्कार में चीन के तत्कालीन

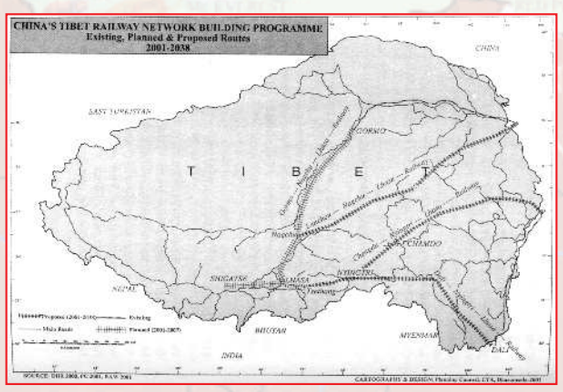

राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने स्वयं ही यह स्पष्ट किया की ल्हासा की ओर जाने वाले रेल मार्ग के निर्माण की आवश्यकता राजनैतिक और सैनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

इस परियोजना के जरिये तिब्बती पठार का चीन द्वारा किया जा रहा सैन्यीकरण बहुत बढ़ जाएगा । इससे चीन और भारत के बीच हथियारों की दौड़ को बढ़ावा मिलेगा और इससे दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया में शक्ति और सुरक्षा का संतुलन बिल्कुल बिगड़ जायेगा।

चीन मीडिया ने संकेत दिया है की रेल मार्ग के जरिए ल्हासा से जुडते ही गोर्मो में सैन्य मौजूदगी कई गुणा बढ़ जाएगी। और साथ ही भारत की सीमा से लगे दक्षिण पश्चिमी तिब्बत के विभिन्न भागों तथा कॉगपो में स्थित सैनिक अडडों के विस्तार को भी बढ़ावा मिलेगा।

रेल परियोजना के पूरा होने पर भारतीय बाजार चीन मे बनी सस्ती चीजों से भर जाएगा जिससे भारत के कुटीर उद्योगों, लधु उधोगों और मध्यम उद्योगों के बन्द होने की नौबत आ जाएगी।

पर्यावरण का विनाश

तिब्बत, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता हैं, एशिया के मध्य में स्थित है। यह उन सभी प्रमुख नदियों का स्त्रोत है जिन पर भारत, नेपाल, भूटान, बांगला देश, पाकिस्तान, म्यनमार, थाईलैण्ड, लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम में रहने वाली एशिया की आधी से आधिक आबादी निर्भर करती हैं।

चीनी एशिया की आधी तिब्बत के पर्यावरण का बड़े ही योजन.बद्ध तरीके से अभूतपूर्व विनाश हो रहा हैं। वहॉ के सम्पन्न वन, पेड़–पौधे, जीव–जन्तु, खनिज तथा जल–संसाधन सभी ऐसे नुकसान और हास को झेल रहे, जिसको कभी दूर नहीं किया जा सकता । तिब्बत के कोमल पर्यावरण के संतुलन के बुरी तरह बिगाड़ दिया गया हैं।

शोध से पता चला हैं कि सन 1985 के अन्त तक चीनी शासन के अधिकारियों ने तिब्बत के सम्पन्न वनों से लगभग 5400 करोड़ डॉलर मूल्य की लकड़ी कटवा डाली। सिर्फ अम्दो प्रान्त में ही 1955 से लगभग 5 करोड़ पेड़ काटे गए और कुल वनों का कम–से–कम 70 प्रतिशत हिस्सा बर्बाद कर दिया। यही स्थिति तिब्बत के अन्य भागों विशेष तौर पर पूर्वी और दक्षिणी तिब्बत में भी रही।

तिब्बत में वनों की इस बर्बादी के कारण चीन सहित अनेक पडोसी देशों में बाढ़ आने लगी। 1987–1988 में भारत के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का योगदान 37 प्रतिशत या उससे भी अधिक था। तिब्बत में हुई वनों की बर्बादी से मानसून के असन्तुलन का खतरा और अधिक बढ़ गया हैं, जिससे भारत की कृषि को बहुत नुकसान पहुॅच सकता हैं।

चीन ने पहले ही ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदी के मार्ग को बदलने की घोषणा कर दी हैं। अगली बारी सिन्धु नदी की हो सकती हैं। और फिर सतलुज नदी की। सक्षेप में, जब तक सम्भव होगा चीन भारत को कमजोर करने की कोशिश करता रहेगा।

कैलाश–मानसरोवर

तिब्बत के बाकी हिस्सों की तरह ही पवित्र कैलाश–मान सरोवर क्षेत्र भी एक सैनिक अडडे में बदलता जा रहा हैं। कैलाश मान सरोवर क्षेत्र उन अनेक नदियों का स्त्रोत हैं जो भारत की ओर बहती हैं। चीन सरकार तिब्बत के धार्मिक स्थलों का प्राकृतिक साधनों की खातिर शोषण कर रही हैं और कैलाश मानसरोवर जैसे स्थलों को अपवित्र कर रही हैं। चीनी शासन विभिन्न प्रकार की पाबंदियों लगा कर भारत के तीर्थ यात्रियों की कैलाश–मानसरोवर की यात्रा को भी मुश्किल बनाता जा रहा हैं।

चीनी आबादी का स्थानांतरण

व्यापक स्तर पर चीनी आबादी के तिब्बत में स्थानांतरण तथा तिब्बती स्त्रियों के जबर्दस्ती गर्भपात और उन्हें बंध्याकरण करने का कार्यवाहियों का भारत पर नकारात्मक भौगोलिक, राजनैतिक तथा कूटनीतिक प्रभाव पड़ेगा। तिब्बत में चीनी आबादी बहुसंख्या में होते ही इसकी मध्यस्थ राज्य की ऐतिहासिक भूमिका सदा के लिए समाप्त हो जाएगी।

आज तिब्बत में बसे 60 लाख तिब्बती लोगों से अधिक आबादी वहॉ चीन से आकर रह रहे 75 लाख चीनी लोगों की हो गई हैं। 1950 से पूर्व वहॉ मुश्किल से ही कोई चीनी दिखाई देता था जबकि आज तिब्बत में चीनी और तिब्बती लोगों का अनुपात लगभग 3:1 हैं।

तिब्बत : एक अवलोकन

- **क्षेत्रफल** : 25 लाख वर्ग कि0 मी0 जो वर्तमान चीन के कुल क्षेत्रफल का 26:04 प्रतिशत हैं।
- **राजधानी** : ल्हासा
- **जनसंख्या** : 60 लाख तिब्बती
- **धर्म** : बौद्ध धर्म, बौन तथा इस्लाम
- **भाषा** : तिब्बती (चीनी कब्जे के कारण सरकारी भाषा चीनी)
- **पर्यावरण सम्बन्धी प्रमुख समस्या** : वनों की अन्धा धुधं कटाई तथा स्तनपायी पशुओं का व्यापक स्तर पर शिकार
- **समुद्र तल से औसत ऊचाई** : 14000 फुट
- **सर्वोच्च पर्वत** : जोमोंलांग्मा / सागरमाथा / एवरेस्ट
- **औसत तापमान** : जुलाई 58 फा, जनवरी 4 फा.
- **मुख्य नादियां** : सांगपो (ब्रह्मपुत्र), यांग्तसे, मैकोंग, सालवीन, हुआंग–हो, सिन्धु तथा सतलुज।
- **अर्थ व्यवस्था** : तिब्बती लोग – मुख्यतः कृषि और पशुपालन, चीनी लोग मुख्यत : सरकारी, वाणिज्य तथा अन्यसेवाओं से सम्बन्धित उपकमों में।
- **प्रान्त** : उ–त्सांग, अम्दो तथा खम
- **सीमान्त देश** : भीतरी मंगोलिया, पूर्वी तुर्किस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा चीन
- **देश के प्रमुख** : महामहिम दलाई लामा
- **जनवादी चीन से सम्बन्ध** : औपनिवेशिक

तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र क्या है ?

यह तथाकथित तिब्बत स्वायत्तशसी क्षेत्र जिसकी रचना 1965 में की गई थी तिब्बत के कुल भू–क्षेत्र के आधे भाग से भी कम है तथा इसकी आबादी का केवल एक तिहाई हिस्सा ही हैं। (वास्तव में